

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 32/2022

रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/52

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गढी,
जिला बांसवाड़ा

अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट:-

1. श्री रमन लाल लबाना पुत्र श्री मलुक चन्द जी निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बांसवाड़ा
2. श्री भंवर लाल पुत्र तारा चन्द निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बांसवाड़ा

बनाम

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 24-03-2023

बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गढी, जिला बांसवाड़ा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री रमन लाल लबाना पुत्र श्री मलुक चन्द जी निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बांसवाड़ा, श्री भंवर लाल पुत्र तारा चन्द निवासी ग्राम चन्दन पुरा, आंजना, तहसील अरथुना जिला बांसवाड़ा को दिनांक 12-03-2008 को राशि रुपया 2,00,000 (अक्षरे दो लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 10.06.2011 को अक्रियान्वित आस्तित्व में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 03.09.2021 तक कुल बकाया राशि 122002 (एक लाख बाईस हजार दो रु.) एवं दिनांक 03.09.2021 से राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्वोरीटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास बंधक

सम्पत्ति की जिसका विवरण आवासीय मकान सर्वे नंबर 4376, ग्राम चन्दनपुरा, आंजना, तहसील अरथुना,

जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 333 वर्गगज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ पूर्व में रोड, पश्चिम



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

म मनीलाल जी का मकान, उत्तर में गौरीशंकर का मकान, दक्षिण में रमेश/ कचरा का मकान है।

जिसका ऋणी ने करार कर ऋण राशि अदायगी हेतु आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 03-09-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित बंधक करार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 12.07.2022 को जारी किये गए। दिनांक 28-09-2022 को अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री राकेश पाटिदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण सं. 1 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा। अप्रार्थी सं.1 के अधिवक्ता को दिनांक 24.03.2023 तक जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जा चुके हैं किन्तु जवाब पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं.2 लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया जाता है एवं अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता की ओर से वहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगणों द्वारा ऋण राशि जमा करवाई जा रही है, सम्पूर्ण राशि जमा कराने कुछ समय दिया



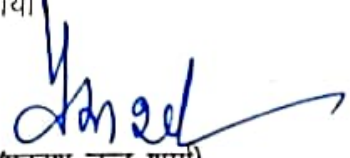

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगणों को समुचित पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। अब और समय दिया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं बैंक व अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002, स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी/ अरथुना को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात बैंक ऑफ बडौदा, शाखा गढी, जिला बॉसवाड़ा को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 24-03-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट
बॉसवाड़ा (राज.)
बॉसवाड़ा